Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

an>

Title : Need to send a Central team to assess the losses incurred due to heavy floods in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, बाढ़ से राजस्थान में भारी जन धन की हानि के सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय दल शीघ्र भेजा जाये। राजस्थान के दक्षिणी तथा पश्चिमी जिलों में विशेातः बाडमेर, पाली सिरोही, जालौर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, कोआ, झालावाड़, राजसमंद आदि जिलों

---

*The speech was laid on the Table.

में अतिवृटि एवं बाढ़ के कारण भारी जन धन की हानि हुयी है। स्वाधीनता दिवस के बाद मूसलाधार बारिश के कारण रेगिस्तानी जिले विशेा रूप से बाढ की लपेट में आ गये हैं ति दक्षिणी जिलों की अनेक बस्तियां जलमग्न होने के साथ ही सडकों, भवनों पुलियों आदि का भारी नुकसान हुआ है। पिछले दो तीन दिन में राजस्थान के पश्चिमी जिलों बाडमेर, जैसलमेर आदि में बाढ से मृतकों की संख्या सैंकड़ों के आसपास पहुंच गयी है। सरकारी आंकडों के अनुसार भी मरने वालों की संख्या 70 से ऊपर हो गयी हे। यद्यपि राजस्थान सरकार ने अपने प्रयासों तथा सेना ने हेलिकॉप्टरों एवं सैनिकों के माध्यम से बचाव कार्य कर सैंकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। बाढ़ से पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, पाली तथा दक्षिणी राजस्थान में करोड़ों रूपये की फसलें तबाह हो चुकी हैं और जो फसलें बची हैं उन पर फसलनाश्क कीटों ने धावा बोल दिया है। राजस्थान में पहले अकाल एवं अब बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वर्ा के कारण कइ गांव बह गये हैं, कई गांवों की फसलें डूब गयी हैं, खरीफ की पूरी फसल चौपट हो चुकी है। अकेले बाड़मेर क्षेत्र में 4 लाख हैक्टेयर में बोई गयी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गयी है। इस अतिवृटि से बाडमेर, जैसलमेर जिलों में 42 करोड़ रूपये का नुकसान हो चुका है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की विकट परिस्थिति को दृटिगत रखते हुए केन्द्रीय सर्वेक्षण टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए अविलंब भेजी जाये, केन्द्रीय आपदा कोा तथा केन्द्रीय आपदा आकस्मिक कोा के पुराने निर्धारित मापदंडों को अविलंब बदला जाये, जनधन की भारी हानि को देखते हुए तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति एवं फसलों की भारी बरबादी को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति राजस्थान को भी अविलंब विशेा सहायता पैकेज घोाित किया जाये तथा केन्द्र की ओर से राजस्थान को मिलने वाली पूर्व बकाया राशि 123 करोड़ रूपये भी शीघ्र प्रदान किये जायें, राजस्थान को उचित मात्रा में गेहूं उ पलब्ध कराया जाये तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुयी सडकों की मरम्मत के लिए अलग से राशि प्रदान की जाये।